

संख्या :- १४७ उत्तीस/०४-२(२२पे०)/२००४

प्रेषक,

बी०पी० पाण्डेय
सचिव, पेयजल,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।
3. निदेशक,
स्वजल परियोजना,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग

देहरादून, दिनांक २६ मई, २००५

विषय: ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता कार्यों के निष्पादन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए पेयजल निगम एवं जल संस्थान से कार्मिक उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

महोदय,

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को पेयजल विभाग से सम्बंधित प्रशासनिक, कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकारों एवं दायित्वों का संक्रमण शासनादेश सं० २१२१/उत्तीस/०४-२/२००४ दिनांक १७ अगस्त २००४ द्वारा किया गया है। उक्त शासनादेश में व्यवस्था की गई है कि उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा निर्मित एकल ग्राम पेयजल योजनाएं एवं हैंड पम्पों से सम्बंधित परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण ग्राम पंचायतों को किया जायेगा, जिनके द्वारा भविष्य में इन योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण किया जायेगा।

२- उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत को प्रशासनिक, कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकारों को संक्रमित करने के कारण, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान से कार्मिकों को

उपलब्ध कराये जाने की तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जाए।

- (1) उत्तरांचल पेयजल निगम तथा जल संस्थान हस्तांतरित किए जाने वाले कार्मिकों को चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करेंगे। वर्तमान में लगभग 2727 योजनाएं जल संस्थान द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं।

अतः इनसे सम्बंधित अंशकालिक चौकीदार तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायतों के अधीन कर दिए जायें। शेष एकल ग्राम योजनाओं से सम्बंधित कार्मिकों को ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने हेतु एक कार्ययोजना शीघ्र तैयार कर शासन को उपलब्ध कराई जाये। स्मरणीय है कि कार्मिकों का हस्तांतरण केवल ग्राम पंचायत स्तर पर ही नहीं होना है अपितु ब्लाक व जिला स्तर भी एकल ग्राम पंचायतों की संख्या व कार्यभार के अनुपात में किया जाना है। अतः तदनुसार अधिकारियों के हस्तांतरण की भी कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत कर दी जाये। एकल ग्राम योजनाओं हेतु हर स्तर के समस्त कार्मिक/अधिकारी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2008 तक कर दिए जायेंगे।

- (2) एकल ग्राम योजनाओं के अन्तर्गत पेयजल निगम एवं जल संस्थान के ग्राम स्तर के कार्मिक ग्राम प्रधान/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेंगे।
- (3) जिला स्तर पर सेक्टर रिफॉर्म सिद्धान्त पर करवाए जा रहे कार्यों से सम्बंधित पेयजल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष के मार्गनिर्देशन पर कार्य करेंगे।
- (4) ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप-समितियों को कार्मिक दिए जाने से पूर्व नई व्यवस्था में उनके दायित्वों व कार्यप्रणाली की जानकारी भी प्रशिक्षण के माध्यम से कार्मिकों को दी जाये। इन प्रशिक्षणों में ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी साथ में प्रशिक्षण दिया जाये। प्रशिक्षण के कार्य को सम्पादित करने का दायित्व परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल

परियोजना का होगा। नियमित कार्मिकों को पंचायतों को हस्तांतरित करते समय यह ध्यान में रखा जाये कि जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति निकट भविष्य में है उन्हें पंचायतों को न दिया जाये, हस्तांतरित किए जाने वाले कार्मिकों का सेवा काल कम से कम 5 वर्ष शेष होना चाहिए। अंशकालिक चौकीदार/दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों पर यह लागू नहीं है।

- (5) कार्मिकों के हस्तांतरण में यह भी ध्यान में रखा जाये कि सर्वप्रथम स्वेच्छा से जाने वाले कार्मिकों को ही पंचायतों को दिया जाये तदोपरान्त यदि आवश्यकता पड़े तो वरिष्ठता के क्रम में पंचायतों को भेजा जाये। ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप-समितियों को कार्मिक दिए जाने के उपरान्त उनके वेतन इत्यादि की व्यवस्था करने का दायित्व सम्बन्धित अधिष्ठान (उत्तरांचल पेयजल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान) का होगा और वे वेतन के लिए पर्याप्त धनराशि माह पूर्ण होने से पूर्व ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप-समितियों के सम्बन्धित पेयजल खाते में जमा करवायेंगे।
- (6) इस प्रकार हस्तांतरित कार्मिकों की गोपनीय प्रविष्टियाँ आदि उत्तरांचल पेयजल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान और स्वजल परियोजना के सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई को सौंपी जायेंगी। इन गोपनीय प्रविष्टियों का पर्यवेक्षण ग्राम प्रधान द्वारा किया जायेगा और स्वीकृति स्वजल परियोजना के सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा दी जायेगी। अतः ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए गये कार्मिकों की सूचना नियमित रूप से स्वजल परियोजना को भी दी जाये।
- (7) पंचायतों के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति सम्बन्धित पंचायत राज संस्था द्वारा दी जायेगी और अर्जित अवकाश की स्वीकृति जिला परियोजना प्रबन्धन द्वारा कर्मियों के विकल्प की व्यवस्था करते हुए दी जायेगी।
- (8) पंचायत के अधीन कर्मियों के विरुद्ध आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही सम्बन्धित पंचायती राज संस्था द्वारा प्रारम्भ की जायेगी व सम्बन्धित जिला

परियोजना प्रबन्धन इकाई को संस्तुति प्रेषित करने पर उक्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

- (9) उपरोक्त व्यवस्था एकल ग्राम योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित ग्रामों के लिए ही लागू होगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

बी०पी० पाण्डेय
सचिव

पृष्ठांकन संख्या 987/उन्तीस/04-2(22पे०)/2004 तददिनांक मई, 2005

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री/पेयजल मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा० मुख्यमंत्री जी/मा० पेयजल मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल, देहरादून।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, उत्तरांचल।
11. निदेशक, एन० आई० सी० देहरादून।
12. वित्त अनुभाग-3।
13. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,


(कुँवर सिंह)
अपर सचिव